दैनिक जागरण 27-06-2018

कार्यशाला | एनएसआइ में जुटे विभिन्न राज्य और संसाधनों के विशेषज्ञों ने किया मंथन, बनाया प्रगति का रोडमैप, सरकार को दिया जाएगा प्रस्ताव

... तो मुस्कुराएंगे गन्ना किसान, बढ़ेगा चीनी उद्योग

जागरण संवाददाता, कानपुर : गन्ना और चीनी के बढ़ते उत्पादन ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। सरप्लस उत्पादन के चलते चीनी के दाम गिर गए और गन्ना किसानों का भुगतान अटक गया। भविष्य में भी उत्पादन बढ़ना संभावित है। इन स्थितियों से निपटते हुए कैसे लाभ लिया जा सकता है, इस पर मंथन के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें शामिल देश भर के विशेषज्ञों ने चीनी उद्योगों और किसानों के लिए रोडमैप तैयार किया।

कार्यशाला को संबोधित करते प्रो. नरेंद्र मोहन • जागरण

संस्थान के सभागार में 'उत्तरी भारत में स्थित शर्करा उद्योग हेतु रोडमैप' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला हुई। एनएसआइ निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि देश में चीनी का कुल उत्पादन लगभग 32 मिलियन टन हुआ है। जिसमें 12 मिलियन टन उत्पादन की सर्वाधिक हिस्सेदारी उत्तरी भारत की चीनी मिलों की रही है। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि देश में चीनी की खपत करीब 25 मिलियन टन है, शेष का निर्यात विश्व बाजार में करने के लिए प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। खपत की तुलना में उत्पादन अधिक होने से चीनी के दाम गिरे हैं। उन्होंने गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल और सह-उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया। गन्ने की खोई से बिजली बनाने का भी सुझाव दिया। साथ ही गन्ना मूल्य निर्धारण का ऐसा फार्मूला बताया, जो विदेशों में प्रचलित है। प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल फार्मूला बनाया है, जिसका प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भी भेजा जाएगा।

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के कुलपति प्रो. सुशील सोलोमन और उप्र गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर के निदेशक डॉ. जे. सिंह ने अपने-अपने वक्तव्य में समान रूप से उत्तर भारत में गन्ने की केवल एक प्रजाति के उत्पादन पर चिंता जताई। सुझाव दिया कि उन्नत प्रजाति के ऐसे विविध गन्नों का उत्पादन करना होगा, जो बीमारियों से भी लड़ सकें। ग्लोबल केन शुगर के प्रबंध निदेशक डॉ. जीएससी राव ने स्पेशल शुगर बनाने और अंतर्फसलीय उत्पादन की जरूरत बताई। कहा कि इसी तरह से किसानों की आय 2022 तक दोगुनी की जा सकती है। भारतीय चीनी मिल एवं उप्र चीनी मिल संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की शीरा संबंधी नीति का मसला उठाया, जिसके कारण बड़ी मात्रा में शीरा चीनी मिलों में पड़ा रहा जाता है।

एनएसआइ में रोडमैप विषय पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित प्रोफेसर • जागरण

सरकार को सौंपा जाएगा यह प्रस्ताव

- गन्ने के मूल्य निर्धारण को राज्य समर्थित मूल्य के स्थान पर हाइब्रिड फार्मूला अपनाया जाए।
- गन्ने की अधिक से अधिक प्रजातियों का विकास पर्यावरणीय परिवर्तन के लिहाज से कराया जाए।
- गन्ने के उत्पादन क्षेत्र को आवश्यकता अनुसार कम कर अंतर्फसलीय खेती बढ़ाई जाए।
- मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जाएं। मसलन, खोई से सर्फेक्टेंट, शीरा से साइट्रिक एसिड, एसीटोन, ग्लिसरॉल और प्रेसमड से बायो सीएनजी बनाई जा सकती है।
- चीनी मिलों में विशेष चीनी, फार्मास्युटिकल शुगर, आइसिंग शुगर, फ्लेवर्ड शुगर, कैस्टर शुगर, ब्यूब शुगर, कैंडी शुगर आदि का उत्पादन किया जाए।

Times of India 27-06-2018

Disposal of molasses, cane price payment discussed at workshop

TIMES NEWS NETWORK

The workshop was organized to work out a strategy for the next crushing season keeping in view surplus sugar production in the country during 2017-18 which is expected to remain surplus during the next crushing season 2018-19

Kanpur: A national workshop on 'Sugar Industry in Northern India — roadmap for crushing season 2019-20' was organized at National Sugar Institute (NSI) in which vice-chancellors, directors of various universities, representative of Indian and UP sugar mills associations and delegates from sugar factories from UP, Bihar and Haryana participated.

The workshop was organized to work out a strategy for the next crushing season keeping in view surplus sugar production in the country during 2017-18 which is expected to remain surplus during the next crushing season 2018-19, problems associated with disposal of molasses and issues related to cane price payment due to depressed sugar prices as compared to cost of production.

Welcoming the delegates, director, National Sugar Institute, Professor Narendra Mohan congratulated the them for significant improvement in sugarcane and sugar productivity in northern India and also UP becoming number one in sugar production with an estimated 12 million tonnes of sugar out of the total estimated total sugar production of about 32 million tonnes in the country which is all time high.

Prof Mohan said that the sugar industry is required to device a road map so as to produce sugar as per consumption patterns. He said utilization of sugarcane for other purposes may be production of ethanol directly from cane juice and utilization of by-products in a better way by producing power from bagasse and ethanol from molasses, which will also require policy interventions and government support.

Dr. Sushil Solomon, vice-chancellor, CSA University of Agriculture and Technology and Dr J Singh, director, UP Council of Sugarcane Research, Shahjahanpur raised concerns about growing dependency of the sugar industry in northern India on one variety only and suggested to develop several varieties, particularly those which can sustain climate changes, water stress and withstand attack of pests and diseases.

Representatives from Indian Sugar Mills Association and UP Sugar Mills Association also raised issues relating to state government policies on molasses due to which huge quantities of molasses is lying un-disposed with the sugar factories with their prices at rock bottom. The matter related to increase in the revenue by producing value-added products from cane juice, molasses and bagasse was also discussed.

र। बुधवार • 27 जून • 2018 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

मांग से अधिक चीनी उत्पादन बनी समस्या

वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा जरूरी

राष्ट्रीय कार्यशाला को सम्बोधित करते राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रो. नरेन्द्र मोहन व कार्यशाला में उपस्थित चीनी विशेषज्ञ। फोटो - एसएनबी

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

देश के घरेलू बाजार में लगभग 25 मिलियन टन चीनी की खपत है। इसके मुकाबले देश में गत वर्ष 2017-18 में चीनी उत्पादन देश की आवश्यकता से अधिक 32 मिलियन टन से भी ज्यादा हुआ। आसन्न चीनी उत्पादन वर्ष में गन्ना उत्पादन में और वृद्धि संभावित है। इस परिदृश्य को देखते हुए चीनी का बेहतर मूल्य हासिल करने के लिए वैश्विक बाजार में स्थान बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी हो गया है। अन्यथा चीनी उद्योग को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

उक्त विचार चीनी उद्योग व मिलों से जुड़े विशेषज्ञों ने मंगलवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में ' उत्तरी भारत में स्थित शर्करा उद्योग हेतु रोडमैप' विषय पर आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किये। कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों-संस्थानों के कुलपति-निदेशक, भारतीय एवं उप्र चीनी मिल संघ के प्रतिनिधियों के साथ ही उप्र, बिहार व हरियाणा स्थित चीनी मिलों के प्रतिनिधिगणों ने भागीदारी की। विशेषज्ञों ने कहा कि आगामी पेराई सत्र 2018-19 की तैयारी शुरू कर दी गयी है। इस सत्र में भी आवश्यकता से अधिक चीनी उत्पादन व शीरे के निस्तारण संबंधी समस्याओं एवं चीनी की घटी हुई कीमतों के कारण चीनी मिल संचालकों के समक्ष किसानों को गन्ने के मूल्य के भुगतान में दिक्कत आ सकती है। इस संकट को कम करने को लेकर कार्यशाला में विचार मंथन किया गया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रो.नरेन्द्र मोहन ने कहा कि शर्करा उद्योग क्षेत्र में ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे बाजार में खपत की मांग के अनुसार चीनी का उत्पादन किया जा सके एवं शेष गन्ने का उपयोग अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार करने में किया जाना चाहिए।

> राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में 'शर्करा उद्योग के रोडमैप' पर कार्यशाला का आयोजन

सीएसए कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि के कुलपति प्रो.सुशील सोलोमन एवं उप्र गन्ना अनुसंधान परिषद, शाहजहांपुर के निदेशक डॉ.जे सिंह ने कहा कि उत्तरी भारत में गन्ने की केवल एक प्रजाति के उत्पादन पर चिंता जतायी व विविध प्रजातियों के उन्नत गन्नों का उत्पादन करने की आवश्यकता बतायी। ग्लोबन केन शुगर के एमडी डॉ.जीएससी राव ने स्पेशल शुगर बनाने व गन्ने के साथ अन्य फसलों के उत्पादन पर जोर दिया।

भारतीय चीनी मिल एवं उप्र चीनी मिल संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की शीरा नीति के मामलों को उठाया। उन्होंने कहा कि समुचित नीति के न होने के चलते चीनी मिलों में काफी मात्रा में मोलोसेस बिना निस्तारित पड़ा रह जाता है। चीनी मिलों के लाभ हेतु गन्ने के रस, खोई व शीरे से मूल्य सवर्धित उत्पादों का उत्पादन कर आय में वृद्धि संबंधी उपायों पर भी चर्चा की गयी।

चीनी उद्योग की बेहतरी के लिए आये कई सुझाव

गन्ना उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में अपनी समस्याओं-मांगों पर मंथन किया व सर्वसम्मति से कुछ सुझाव भी दिये गये। मसलन-गन्ने के मूल्य निर्धारण हेतु स्टेड एडवाइज्ड प्राइस के स्थान पर एक हाईब्रिड फार्मूले का विकास करना, बदलते पर्यावरण के अनुरूप गन्ने के अधिक से अधिक प्रजातियों के विकास, गन्ने के उत्पादन क्षेत्र को आवश्यकतानुसार कम करना तथा गन्ने की फसल के साथ दूसरी फसल के उत्पादन को बढ़ावा देना, चीनी के खपत एवं उत्पादन में संतुलन, गन्ने के रस एवं बी हैवी मोलासेस से चीनी के स्थान पर इथेनाल बनाना, खोई से सर्फक्टेंट बनाना, मोलासेस से साइट्रिक एसिड, एसीटोन, ग्लिसराल एवं प्रेसमड से बायो सीएनजी बनाने, वर्तमान चीनी मिलों में रॉ एवं रिफाइंड चीनी बनाने के प्रॉसेस में परिवर्तन करना तथा फार्मास्यूटिकल शुगर, आईसिंग शुगर, फ्लेवर्ड शुगर, कैस्टर शुगर, क्यूब शुगर व कैंडी शुगर जैसे उत्पाद तैयार करने को बढ़ावा देना।

अमर उजाला 27-06-2018

हाइब्रिड फार्मूले से तय होगा गन्ने का दाम

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर। गन्ना किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिले इसके लिए देशभर के गन्ना वैज्ञानिकों ने मिलकर हाइब्रिड फार्मूला तैयार किया है। मंगलवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में इस फार्मूले के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। अब इसे एनएसआई की ओर से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि अभी यूपी, बिहार, उत्तरांचल, हरियाणा में गन्ने का दाम राज्य सरकारें गन्ने के वजन के अनुसार तय कर देती हैं। इससे किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। जबकि गन्ने का दाम क्वालिटी सहित कुछ अन्य मानकों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। प्रो. नरेंद्र ने बताया कि हाइब्रिड फार्मूले के अनुसार सबसे पहले गन्ने की क्वालिटी देखी जाएगी। इसके बाद गन्ने से तैयार होने वाली चीनी व अन्य उत्पादों से होने वाली कुल आय की गणना होनी चाहिए और अंतिम मानक में फैक्ट्री की दक्षता परखनी होगी। मतलब अगर कोई फैक्ट्री कम चीनी उत्पाद करती है तो इसका खामियाजा किसान को न भुगतना पड़े इसका भी फार्मूले में ख्याल रखा गया है। प्रो. नरेंद्र मोहन ने बताया कि ऐसा ही फार्मूला ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड सहित कई देशों में लागू है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के कुलपति प्रो. सुशील सोलोमन ने उत्तरी भारत में गन्ने के उत्पादन के तौर-तरीकों पर चिंता व्यक्त की। कहा कि यहां केवल गन्ने की एक प्रजाति का उत्पादन होता है।

किसानों को चाहिए कि वह विविध प्रजाति का उत्पादन करें तारी गन्ने में भी वेरायटी आ सके। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर के निदेशक डॉ. जे सिंह, ग्लोबलकेन शुगर के प्रबंध निदेशक डॉ. जीएससी राव सहित देशभर के कई वैज्ञानिकों ने शिरकत की।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन।

27-06-2018

चीनी की कीमतें घटने से आ सकती भुगतान में समस्या

किया मंथन

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

घरेलू बाजार में चीनी की सिर्फ 25 मिलियन टन की जरूरत है। बाकी चीनी वैश्विक बाजार की पूर्ति के लिए होनी चाहिए। इसके लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करनी होगी। चीनी की घटी कीमतों से गन्ना किसानों के भगुतान में समस्या खड़ी हो सकती है। नए पेराई सत्र में सभी बिंदुओं पर गौर करने की जरूरत होगी। यह बातें राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रो. नरेन्द्र मोहन ने कही।

वह संस्थान में पेराई सत्र 2019-20 के लिए उत्तरी भारत में स्थित शर्करा उद्योग हेतु रोडमैप विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। कहा गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तरी भारत ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। देश में कुल उत्पादित चीनी लगभग 32 मिलियन टन हुई है जिसमें 12 मिलियन टन चीनी उत्पादन उत्तर भारत ने किया है। वर्तमान व्यवस्था में गन्ने की कीमत का भुगतान वजन के आधार पर होता है। कहा संस्थान ने भारतीय परस्थितिथियों के अनुकूल एक फार्मूला विकसित किया है जिसे जल्द ही भारत सरकार को भेजा जाएगा। डा. सुशील सोलोमन, कुलपति सीएसए एवं डा. जे. सिंह, निदेशक, उ.प्र. गन्ना अनुसंधान परिषद, शाहजहांपुर ने उत्तरी भारत में गन्ने की केवल एक प्रजाति के उत्पादन पर चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया। डा. जी.एस.सी. राव, प्रबंध निदेशक, ग्लोबलकेन शुगर ने स्पेशल शुगर बनाने एवं गन्ने के साथ अन्य फसलों के उत्पादन पर जोर दिया।

बाजार में खपत के हिसाब से बदलें रणनीति

शर्करा उद्योग को ऐसे कदम उठाए, जिससे मांग के अनुसार चीनी का उत्पादन हो सके। गन्ने के जूस से सीधे इथेनाल के उत्पादन और सह-उत्पादों का बेहतर उपयोग हो। गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन एवं शीरे से इथेनाल उत्पादन बनाने की जरूरत है। भारतीय चीनी मिल एवं उ.प्र. चीनी मिल संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की शीरा संबंधी नीति को उठाया जिससे काफी मात्र में मोलासेस बिना निस्तारित किए हुए चीनी मिलों में पड़ा रह जाता है।

यह प्रस्ताव तैयार किए गए

- गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए स्टेट एडवाइज्ड प्राइस के स्थान पर एक हाइब्रिड फार्मूले का विकास
- गन्ने की अधिक से अधिक प्रजातियों का विकास, जो कि पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुसार अपने आपको ढाल सकें
- गन्ने के उत्पादन क्षेत्र को आवश्कतानुसार कम करना तथा एक फसल के साथ दूसरी फसल (अंतर्फसलीय) फसलों के उत्पादन की आवश्यकता
- चीनी के खपत एवं उत्पादन में संतुलन रखना जैसे कि गन्ने के रस एवं बी हैवी मोलासेस को चीनी के स्थान पर इथेनाल बनाने हेतु उपयोग
- मूल्य संवर्धित उत्पादों का उत्पादन जैसे खोई से सर्फक्टेंट बनाना तथा मोलासेस से साइट्रिक एसिड, एसीटोन, ग्लिसराल एवं प्रेसमड से बायो सीएनजी बनाना
- चीनी मिलों में कच्ची एवं रिफाइंड चीनी बनाने हेतु प्रोसेस में वांछनीय परिवर्तन
- चीनी उत्पाद जैसे कि फार्मास्युटिकल शुगर, आइसिंग शुगर, फ्लेवर्ड शुगर, कैस्टर शुगर, क्यूब शुगर और कैंडी शुगर का उत्पादन।

The Pioneer 27-06-2018

Workshop on sugar industry held

PIONEER NEWS SERVICE ■ KANPUR

The Director of National Sugar Institute, Prof Narendra Mohan, while addressing a national workshop on 'Sugar Industry in Northern India: Road Map for crushing season' at the Institute auditorium on Tuesday emphasised the need for significant improvement in the sugarcane and sugar productivity in northern India and also Uttar Pradesh becoming no 1 in sugar production with an estimated 12 million tonnes of sugar out of the total estimated total sugar production of about 32 million tonnes in the country which was all time high.

He however raised concerns about such a high sugar production keeping in view domestic consumption of about 25 million tonnes only and issues related to liquidity of sugar in the world market.

He said the sugar industry required a device road map so as to produce sugar as per consumption patterns, look at utilisation of sugarcane for other purposes may be production of ethanol directly from cane juice and utilisation of by-products in a better way by producing power from bagasse and ethanol from molasses, which will also require policy interventions and government support.

He also stressed upon developing a logical cane price fixation formula having elements of revenue generation, sugarcane quality and factory efficiency as the present system of paying price of sugarcane on the basis of weight irrespective of its quality or the sugar prices was not considered rational. He said such formula's were prevalent in other sugar producing countries.

He said under Indian conditions, the country had developed a formula about the same and a proposal shall be sent to the Government of India also for consideration.

Addressing the workshop the chief guest Dr Sushil Solomon, Vice-Chancellor, CSA University of Agriculture and Technology raised concern over growing dependency of the sugar industry in north India especially on one variety only and mooted the development of several varieties particularly which can sustain climate changes, water stress and withstand attacks of pests and diseases.

Dr GSC Rao, Managing Director, Global Canesugar Services Pvt. Ltd. emphasised on branding of sugars and for intercropping of other crops along with sugarcane so as to enhance the income of the farmers and to make it double by 2022.

He said if such practice was followed, the revenue from the same land area will increase and farmers shall not stress upon increasing price of sugarcane arbitrarily every time. Representatives from Indian Sugar Mills Association and UP Sugar Mills Association also raised the issues relating to state government policies on molasses due to which huge quantities of molasses was lying undisposed with the sugar factories with their prices at rock bottom.

He said the matter related to increase in the revenue by producing value added products from cane juice, molasses and bagasse was also discussed.

At the end of the workshop, following was considered essential for the sugar industry in northern India for its sustainability. Implementation of a hybrid formula for sugarcane price payment rather than on the basis of state advised price. Secondly development of several sugarcane varieties which can withstand climate change and also to lower dependency on a single variety.

Thirdly limiting the area under sugarcane cultivation, promoting intercropping so as to enhance income of sugarcane farmers.

Emphasis was also laid on balancing the sugar demand-supply situation, diversion of juice or B-heavy molasses to reduce sugar production and enhance ethanol production for which government support shall be required.

Besides production of value added products e.g. surfactant from bagasse, citric acid, acetone, yeast and glycerol through molasses, wax and bio-CNG from press mud and finally exploring possibilities of converting existing process and production of plantation white sugar so as to produce raw and refined sugars.

He said other special sugars pharmaceutical sugar, icing sugar, flavoured sugars, castor sugar, cube and candy sugar to be provided for generating higher revenues.

Delegates from sugar factories from UP, Bihar and Haryana participated and the workshop was organised to work out strategy for the next crushing season keeping in view the surplus sugar production in the country during 2017-18 and expected to remain surplus during next crushing season 2018-19, problems associated with disposal of molasses and issues related to cane price payment due to depressed sugar prices was compared to cost of production.